सोंदुर गोपाल

बनाम

सोंदुर रजीनी

(सिविल अपील संख्या 4629, 2005)

15 जुलाई 2013

[चंद्रमौलि के.आर. प्रसाद और वी गोपाल गौड़ा, जे.जे.]

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-एस.एस. 1(2), 2(1) और 10-अधिनियम का विस्तार और प्रयोज्यता- राज्य क्षेत्रातीत विस्तार बच्चों की अभिरक्षा व न्यायिक अलगाव के लिए पत्नी की याचिका पति द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई कि पत्रकारो का भारत में कोई अधिवास नहीं था और, इसलिए, अधिनियम द्वारा शासित नहीं थे- माना गया: अधिनियम राज्य क्षेत्रातीत विस्तार और यह भारत में अधिवास वाले हिंदुओं पर लागू होता है, भले ही वे भारत से बाहर रहते हों। यदि भारत में निवास की आवश्यकता पूरी तरह से हटा दी जाती है, तो अधिनियम का कोई संबंध भारत के साथ नहीं होगा, जिससे अधिनियम इस आधार पर कमजोर होगा कि राज्यक्षेत्रातीत विस्तार का भारत के साथ कोई संबंध नहीं है। मूल निवास तब तक कायम रहता है जब तक कि न केवल एक और अधिवास प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि इसे मूल अधिवास को छोड़ने का इरादा प्रकट करना चाहिए-जब तक कि अन्यथा साबित न हो, अधिवास परिवर्तन

के विरुद्ध उपधारणा ली जावेगी। इसलिए, आरोप लगाने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि-इरादा हमेशा दिमाग में रहता है, जिसका अनुमान ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी कार्य, घटना या परिस्थिति की तथ्यों से लगाया जा सकता है- ऑस्ट्रेलिया के निवासी होने के पति के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं-उस मामले के लिए, पति, पत्नी और बच्चों ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता हासिल नहीं की-दावा की पति ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से निवास करना चाहता था, उपलब्ध सामग्री के सामने, मात्र एक सपना कहा जा सकता है- इससे वहां स्थायी रूप से निवास करने का उनका इरादा स्थापित नहीं होता है-इसके अलावा, इस बारे में कोई कथन नहीं कि पति ने कैसे और किस तरह से मूल निवास स्थान को छोड़ दिया- पति का मूल निवास स्थान यानी भारत बना रहा- पति और पत्नी दोनों भारत के निवासी होने के कारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते थे-इसलिए पत्नी द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य थी-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 245(2)।

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून-अधिवास-प्रकार-मूल निवास और पसंद का अधिवास-चर्चा की गई।

प्रतिवादी-पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत अपीलकर्ता-पति से न्यायिक अलगाव और उनके दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की।

अपीलकर्ता-पति ने इस आधार पर याचिका की पोषनीयता पर सवाल उठाते हुए अंतरिम आवेदन दायर किया कि पार्टियों का भारत में कोई अधिवास नहीं था और इसलिए, वे हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा शासित नहीं थे। पति ने दलील दी कि दोनों पक्ष स्वीडन के नागरिक हैं और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो उनकी पसंद का निवास स्थान है और उन्होंने मूल निवास स्थान यानी भारत को छोड़ दिया है, परिवार न्यायालय, मुंबई का क्षेत्राधिकार धारा 1(2) हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वर्जित है।

फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता-पति के आवेदन को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी-पत्नी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। अपील में, उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी-पत्नी द्वारा दायर याचिका को पोषनीय माना। उच्च न्यायालय ने माना कि पति यह स्थापित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा कि उसने कभी भी भारतीय अधिवास को त्याग दिया था और/या अपनी पसंद का अधिवास प्राप्त करने का इरादा रखता था और यह मान भी लिया जाए कि पति ने अपने मूल अधिवास को त्याग दिया था और नागरिकता के साथ-साथ स्वीडन का अधिवास प्राप्त कर लिया था, जब वे ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित हुए तो उन्होंने स्वीडन का अधिवास छोड़ दिया और इस प्रकार भारत का अधिवास पुनर्जीवित हो गया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना:

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 1(2) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसका राज्यक्षेत्रातीत विस्तार है। एक कानून जिसका राज्यक्षेत्रातीत विस्तार है, उसे सीधे दूसरे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कानून अमान्य नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 (2) द्वारा संरक्षित है। अनुच्छेद 245(2) में प्रावधान है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि इसका संचालन राज्यक्षेत्रातीत होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यक्षेत्रातीत वाला कानून ऐसा बनाया जा सकता है जिसका भारत के साथ कोई संबंध नहीं है। जब तक ऐसी आकस्मिकता मौजूद न हो, संसद राज्यक्षेत्रातीत विस्तार वाला कानून बनाने में अक्षम होगी। [पैरा 13] [719-एफ-एच; 720-ए-बी]

मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त एवं अन्य। 1989 सप्लीमेंट (2) एससीसी 642: 1989 (2) एससीआर 994 -

02. अधिनियम की धारा 1(2) से यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत के हिंदुओं पर लागू होता है और यह भारत में रहने वाले उन हिंदुओं पर भी लागू होता है जिसका

अधिवास भारत में है व उक्त क्षेत्र से बाहर हैं। संक्षेप में, यह अधिनियम भारत में रहने वाले हिंदुओं पर लागू होगा, भले ही वे भारत से बाहर रहते हों। यदि भारत में निवास की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, तो अधिनियम का भारत के साथ कोई संबंध नहीं होगा जो इस आधार पर अधिनियम को कमजोर बना देगा कि राज्यक्षेत्रातीत विस्तार का भारत के साथ कोई संबंध नहीं है। कानून के इस राज्यक्षेत्रातीत विस्तार को हिंदुओं के साथ संबंध के कारण नहीं बल्कि भारत से अधिवास वाले हिंदुओं के कारण संरक्षित किया गया है। [पैरा 14] [720-ई-जी]

03. यह कहने के लिए कि अधिनियम हिंदुओं पर लागू होता है, भले ही उनका अधिवास कोई भी हो, इस अधिनियम के राज्यक्षेत्रातीत को बिना किसी संबंध के पूरी दुनिया में विस्तारित करता है, जिसकी व्याख्या यदि अनुमोदित हो जाती है, तो ऐसा प्रावधान अमान्य हो जाएगा। इसके अलावा, इससे अधिनियम की धारा 1(2) में "अधिवासित" शब्द निरर्थक हो जाएगा। विधायिका आमतौर पर अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करती, यह व्याख्या का एक स्वीकृत सिद्धांत है। कोई अन्य व्याख्या 'अधिवासित' शब्द को निरर्थक बना देगी। [पैरा 16] [721-एफ-एच; 722-ए]

प्रेम सिंह बनाम श्रीमती दुलारी बाई एवं अन्य। एआईआर 1973 कैल. 425; वरिन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य आरएलडब्ल्यू

2005(3) राज. 1791 और विनया नायर और अन्य बनाम कोच्चि निगम एआईआर 2006 केर. 275 रद्द किया गया।

नितबेन बनाम धीरेंद्र चंद्रकांत शुक्ला एवं अन्य। 1 (1984) डी.एम.सी.252-संदर्भित।

04. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2(1) के अंतर्गत अधिनियम के लागू होने का प्रावधान है। यह धारा किसी भी रूप में धर्म के अनुसार हिंदू या विस्तारित अर्थ यानी बौद्ध, जैन या सिख और वास्तव में, देश में रहने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों पर जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हो अधिनियम के लागू होने के संबंध में बताती है। जब तक यह साबित न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रथा या प्रथा के तहत अधिनियम द्वारा शासित नहीं होते हैं। इसलिए, धारा 2 हिंदुओं पर तब लागू होगी जब अधिनियम की धारा 1 के संदर्भ में अधिनियम उस क्षेत्र तक विस्तारित होगा। इसलिए, यह अधिनियम भारत के क्षेत्र के बाहर के हिंदू पर तभी लागू होगा जब ऐसा कोई हिंदू भारत के क्षेत्र में अधिवासित हो। [पैरा 19,20] [722-जी; 723-सी-ई]

05. अपीलकर्ता का यह विशिष्ट मामला है कि वह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला स्वीडिश नागरिक है और इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा। सफल होने के लिए, अपीलकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि वह ऑस्ट्रेलिया का निवासी है और, वह तीसरा मामला नहीं

रख सकता, जब तक साबित नहीं होता है कि वह ऑस्ट्रेलिया का निवासी है, व उसकी पसंद का अधिवास, यानी स्वीडन, पुनर्जीवित हो जाता है। कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में, कानून वैकल्पिक याचिका दायर करने की अनुमति देता है लेकिन वर्तमान मामले के तथ्य पति को इसकी अनुमति नहीं देते हैं। पति ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 1989 में शादी के समय वह स्वीडन का निवासी था, लेकिन यह उसका मामला नहीं है कि वह स्वीडिश कानून द्वारा शासित होगा या स्वीडिश अदालतों का क्षेत्राधिकार होगा। उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता स्वीडन का अधिवासी होने का दावा नहीं करता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का अधिवासी होने का दावा करता है और इसलिए, एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया अपीलकर्ता की पसंद का अधिवास है। [पैरा 22, 24, 25] [724-डी-एफ; 725-सी, ई]

06. अधिवास तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात मूल निवास, कानून के क्रियान्वयन द्वारा अधिवास और पसंद का अधिवास। वर्तमान मामला केवल मूल अधिवास स्थान और पसंद के अधिवास स्थान से संबंधित है। मूल अधिवास स्थान आवश्यक रूप से जन्म स्थान नहीं है। माता-पिता की उनके मूल अधिवास से अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान किसी स्थान पर बच्चे का जन्म होने पर जन्म स्थान बच्चे का अधिवास स्थान नहीं माना जाएगा। पसंद के अधिवास में एक को छोड़ दिया जाता है और दूसरा अधिवास प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन उसके लिए दूसरे अधिवास का

अधिग्रहण पर्यास नहीं होता है। मूल निवास तब तक कायम रहता है जब तक न केवल दूसरा अधिवास प्राप्त कर लिया जाता है, बल्कि मूल अधिवास को छोड़ने का इरादा भी प्रकट होना चाहिए। [पैरा 26] [725-एफ-जी]

7.1. यह स्थापित करने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया उनकी पसंद का अधिवास है, पति ने 18 महीने की अवधि के लिए 25.01.2003 के अपने आवासीय किरायेदारी समझौते पर भरोसा किया है; अप्रैल, 2003 में वार्रावी पब्लिक स्कूल में एक बच्चे का नामांकन; अक्टूबर-नवंबर, 2003 के दौरान स्थायी निवासी का दर्जा के लिए कार्यवाही शुरू और पति-पत्नि द्वारा दिनांक 11.11.2003 को ऑस्ट्रेलिया में अपना स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करना। [पैरा 26] [725-एच; 726-ए-बी]

7.2. जन्म के अधिवास को बदलने का अधिकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध है जो कानूनी रूप से आश्रित नहीं है और ऐसा व्यक्ति पसंद का अधिवास प्राप्त कर सकता है। यह पसंद के देश में अनिश्चित काल तक निवास जारी रखने के इरादे से रहकर किया जाता है। जब तक सिद्ध न हो, निवास स्थान परिवर्तन के विरुद्ध उपधारणा है। इसलिए आरोप लगाने वाले को यह साबित करना होगा। इरादा हमेशा दिमाग में रहता है, जिसका अनुमान ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी कार्य, घटना या परिस्थिति से लगाया जा सकता है। लंबी अवधि के लिए निवास, ऐसे इरादे का प्रमाण है और राष्ट्रीयता में परिवर्तन भी। [पैरा 27] [726-सी-डी]

7.3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जब पति के ऑस्ट्रेलिया के अधिवासी होने के दावे पर विचार करते है, तो इस दलील का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती है। पति ने जिस आवासीय किरायेदारी समझौते पर भरोसा किया वह केवल 18 महीने के लिए है जिसे लंबी अवधि के लिए नहीं कहा जा सकता। माना कि, पति या उस मामले में, पत्नी और बच्चों ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता हासिल नहीं की है। इसके अभाव में, यह स्वीकार करना कठिन है कि उनका इरादा ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से निवास करने का था। उपलब्ध सामग्री के सामने यह दावा कि पति ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से निवास करना चाहता था, केवल एक सपना ही कहा जा सकता है। इससे वहां स्थायी रूप से निवास करने का उनका इरादा स्थापित नहीं होता है।' पति ने स्वीकार किया है कि उसका वीज़ा और कुछ नहीं बल्कि एक "दीर्घकालिक परमिट" था और "कोई अधिवास दस्तावेज़ नहीं"। इतना ही नहीं, इस बात का भी कोई कथन नहीं है कि पति ने मूल अधिवास को कैसे और किस तरह छोड़ दिया। इसके सामने, पति के मामले को स्वीकार करना मुश्किल है कि वह ऑस्ट्रेलिया का निवासी है और वह भारत का मूल अधिवास बना रहेगा। पति और पत्नी दोनों भारत के निवासी हैं और इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत होंगे। [पैरा 28] [726-ई-एच; 727-बी]

केस कानून संदर्भ:

एआईआर 1973 कैल. 425 (आेवररूल्ड) पैरा 8, 16

(1984) डी.एम.सी.252 (रेफर्ड टू) पैरा 9, 17

2005(3) राज. 1791 (ओवररूल्ड) पैरा 10, 18

एआईआर 2006 केर। 275 (ओवररूल्ड) पैरा 11

1989 (2) एससीआर 994 (रिलाइड ऑन) पैरा 13

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या.4629/2005।

फैमिली कोर्ट अपील संख्या 11/2005 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.04.2005।

साथ

सी.ए. 2007 की संख्या 487.

वी. गिरी, वाई.एच. मुछला, हुज़ेफा अहमदी, लिज़ माठेव, ऍम.एफ. फिलिप, एजाज़ मकबूल, शालिनी प्रसाद, मृगंक प्रभाकर, एफ.तनिमा किशोर, रोहन शर्मा अपीलार्थी

कोर्ट का फैसला "चंद्रमौलि के आर प्रसाद.जे.'' द्वारा सुनाया गया।

सिविल अपील संख्या 4629/2005

01. अपीलकर्ता-पति, 11 अप्रैल, 2005 के फैसले और आदेश से व्यथित होकर, बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा फैमिली कोर्ट अपील संख्या 11, 2005 में पारित किए गए, जिसमें 1 जनवरी के फैसले और

आदेश को उलट दिया गया था। 2005 में फ़ैमिली कोर्ट, मुंबई, बांद्रा द्वारा अंतरिम आवेदन संख्या 235 ऑफ़ 2004 में याचिका संख्या A-531 ऑफ़ 2004 में पारित किया गया, जो न्यायालय की अनुमति से हमारे सामने है।

02. बिना अनावश्यक विवरणों के तथ्यों जिनसे प्रस्तुत वर्तमान अपील उत्पन्न हुई वे यह है कि अपीलकर्ता- पति व प्रतिवादी-पत्नी के बीच 1989 बैंगलोर में दिनांक 25 जून को हिंदू संस्कार के अनुसार विवाह हुआ जो हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान के तहत पंजीकृत भी हुआ। शादी के बाद पहले ही हफ्ते में पति स्वीडन चला गया जुलाई, 1989 में व पत्नी भी नवंबर, 1989 में गई उन्हें नताशा और स्मियान नाम के दो बच्चे हुए। नताशा का जन्म 19 सितंबर 1993 को स्वीडन में हुआ था। वह डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है। उन्होंने एक घर खरीदा दिसंबर, 1993 में स्टॉकहोम, स्वीडन में। इसके बाद, युगल ने स्वीडिश नागरिकता के लिए आवेदन किया जो उन्हें 1997 में प्रदान की गई। जून, 1997 में, यह जोड़ा मुंबई चला गया, पत्नी के मुताबिक, पति का मालिक भारत में अपना कारोबार स्थापित कर रहा था। यह जोड़ा बच्चे नताशा के साथ जून, 1997 और 1999 के मध्य के बीच भारत में रहे। 1999 के मध्य में, पति के मालिक ने उन्हें सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी की पेशकश की जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और तदनुसार सिडनी, ऑस्ट्रेलिया चले गए। दंपति और बच्ची नताशा स्पोन्सरशिप वीज़ा पर सिडनी गए। जिसमें उन्हें 4 वर्ष की अवधि

के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनुमति दी। जब वे वर्ष 2000 में ऑस्ट्रेलिया में थे, पति ने उस घर को बेचान कर दिया जो उन्होंने स्टॉकहोम, स्वीडन में खरीदा था। दूसरे बच्चे, स्मियान का जन्म 9 फरवरी, 2001 सिडनी में हुआ। 7 जुलाई को पति की नौकरी चली गई और चूँकि अब उनके पास कोई स्पोन्सरशिप नहीं थी, इसलिए उन्हें जनवरी, 2002 के दूसरे सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा। दंपत्ति और बच्चे स्टॉकहोम में स्थानांतरित हो गए और पटटे पर मकान लेकर अक्टूबर, 2002 तक रहे। इस दौरान पति के पास कोई नौकरी नहीं थी। 2 अक्टूबर 2002 को पति सिडनी में दूसरी नौकरी मिल गई और वह उस कार्य हेतु 18 दिसंबर, 2002 को चला गया। लेकिन उससे पहले 14 दिसंबर, 2002 को पत्नी बच्चों सहित मुंबई चली गईं। बाद में, 31 जनवरी, 2003 को पत्नी और बच्चे अपीलकर्ता-पति के पास ऑस्ट्रेलिया चले गए। हालाँकि, पत्नी और बच्चे 17 दिसंबर, 2003 को पर्यटक वीजा पर भारत वापस आ गए जबकि पति सिडनी में ही रुक गया। पति के अनुसार, जनवरी, 2004 में उसकी पत्नी ने उसे सूचित किया कि वह बिल्कुल भी सिडनी नहीं लौटना चाहती है और उसके अनुसार, वह भारत वापस आया और अपनी पत्नी को सिडनी वापस अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की। पति के अनुसार वह सफल नहीं हुआ और अंततः पत्नी ने फ़ैमिली कोर्ट, बांद्रा के समक्ष याचिका दायर की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हिंदू विवाह अधिनियम

की धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव की डिक्री और नाबालिग बच्चों नताशा और स्मियान की अभिरक्षा की मांग की गई।

03. नोटिस मिलने के बाद, पति फैमिली कोर्ट के सामने पेश हुआ और याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया। पति के अनुसार, वे भारत के मूल नागरिक थे, लेकिन उन्होंने "वर्ष 1996-1999 में स्वीडन की नागरिकता हासिल कर ली और स्वीडन के नागरिक के रूप में ऑस्ट्रेलिया में निवास किया"। पति के अनुसार, पत्नी बच्चों के साथ 17 दिसंबर, 2003 को छह महीने की अवधि के लिए ''नोन एक्टेंडेबल पर्यटक वीजा पर भारत पहुंची और उन्होंने 27 जनवरी, 2004 को सिडनी लौटने के लिए हवाई टिकट कन्फर्म की थी।" और इसलिए, "पार्टियों का भारत में कोई अधिवास नहीं है और इसलिए, पार्टियां हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगी"। पति के अनुसार, "स्वीडन की नागरिकता स्वीकार करने वाले पक्षों को यह माना जाएगा कि उन्होंने अपना मूल अधिवास, यानी भारत छोड़ दिया है" और निवास और स्थायी या अनिश्चित निवास के इरादे के संयोजन से पसंद का अधिवास हासिल कर लिया है। पति ने यह भी दावा किया है कि पत्नी का जो अधिवास होगा वह पति का होगा और चूंकि उन्होंने अपने मूल अधिवास को छोड़ दिया है और भारत के क्षेत्रों के बाहर पसंद का अधिवास हासिल कर लिया है, इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उन्हें नतीजा स्वरूप पत्नी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायिक

अलगाव व बच्चों की अभिरक्षा पोषनीय नहीं है। पति के अनुसार, उसका "पसंद का अधिवास अर्थात् ऑस्ट्रेलियाई अधिवास छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और न ही पार्टियों ने पसंद का तीसरा अधिवास प्राप्त किया है या मूल अधिवास को फिर से शुरू किया है" और, इसलिए, हिंदू विवाह के प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा। कुल मिलाकर, पति की दलील यह है कि वे स्वीडन के नागरिक हैं और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के अधिवासी हैं, जो उनकी पसंद का निवास स्थान है और उन्होंने मूल निवास स्थान यानी भारत को छोड़ दिया है, परिवार न्यायालय, मुंबई का क्षेत्राधिकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1(2) के प्रावधानानुसार वर्जित है।

04. इसके विपरीत, पत्नी द्वारा दायर मामला यह है कि उनका मूल निवास स्थान भारत है और इसे कभी भी छोड़ा या त्यागा नहीं गया, हालांकि उन्होंने स्वीडन की नागरिकता हासिल कर ली और फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए। पत्नी के अनुसार, भले ही यह मान लिया जाए कि पति ने स्वीडन में अधिवास प्राप्त कर लिया था, उसने कभी भी अपना अधिवास नहीं बदला और भारत की ही अधिवासी रही। पत्नी ने एक और वैकल्पिक याचिका लगाई है। उनके अनुसार, भले ही यह मान लिया जाए कि उन्होंने भी स्वीडन का अधिवास प्राप्त कर लिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित होने पर दोनों ने इसे छोड़ दिया था और इसलिए, उनका मूल अधिवास, यानी भारत का निवास पुनर्जीवित हो गया। संक्षेप में, पत्नी का मामला यह है कि वह और उसका पति दोनों भारत में रहते हैं और

इसलिए, मुंबई में फैमिली कोर्ट के पास न्यायिक अलगाव और बच्चों की अभिरक्षा के लिए उसके द्वारा दायर याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है।

05. पति ने अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य का हलफनामा दायर किया और पत्नी द्वारा उससे जिरह भी की गई। पति के अनुसार, "शादी से पहले भी उन्होंने 1985 के वसंत में स्टॉकहोम, स्वीडन का दौरा किया था" और "उस स्थान की असाधारण सुंदरता और लोगों की गर्मजोशी और मित्रता ने उन्हें तुरंत प्रभावित किया"। पति के अनुसार, पहला विचार जो उनके मन में आया वह यह था कि "स्टॉकहोम वह जगह है जहाँ" वह "जीना और मरना चाहते थे"। उनके साक्ष्य के अनुसार, 1989 में शादी के समय वह स्वीडन के निवासी थे। इससे पति शायद यह बताना चाहता है कि उसने अपने जन्म के निवास स्थान, यानी भारत को छोड़ दिया और स्वीडन को पसंद के निवास स्थान के रूप में हासिल कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि "पत्नी की अंग्रेजी भाषी देश में रहने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए" उन्होंने "सिडनी, ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया"। उनका विशिष्ट प्रमाण यह है कि "यहां पक्षकार ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले स्वीडिश नागरिक हैं", इसलिए, पति के अनुसार, "केवल ऑस्ट्रेलिया की अदालतों के पास इस प्रकृति की याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा"। पति ने आगे दावा किया है कि "5 अप्रैल, 2004 को, जिस दिन पत्नी ने याचिका दायर की थी" उसने "सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के

अधिवास का दर्जा हासिल कर लिया था"। जहां तक जिरह की तारीख, यानी 17.11.2004 को अधिवास स्थिति का संबंध है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का अधिवास होने पर जोर दिया। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जिस दिन पति ने ऑस्ट्रेलिया का अधिवासी होने का दावा किया, यानी 05.04.2004 को वह उस देश का नागरिक नहीं था या ना ही कभी था, लेकिन उसके पास 457 वीज़ा था, जो कि उसके अपने साक्ष्य के अनुसार एक दीर्घकालिक व्यवसाय परमिट है और यह कोई अधिवास दस्तावेज़ नहीं है"।

6. पारिवारिक अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, पति द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। ऐसा करते समय, पारिवारिक अदालत ने कहा कि "यह नहीं माना जा सकता" कि "पति ने कभी भी अपना मूल निवास स्थान, यानी भारत नहीं छोड़ा है।" हालाँकि, अपील में, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है और पत्नी द्वारा दायर याचिका को कायम रखा है। ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय ने माना कि "पति यह स्थापित करने में बुरी तरह से विफल रहा है कि उसने कभी भी भारतीय अधिवास छोड़ा था और/या अपनी पसंद का अधिवास प्राप्त करने का इरादा रखता था"। यह मानते हुए भी कि पति ने अपने मूल निवास को छोड़ दिया था और नागरिकता के साथ-साथ स्वीडन का अधिवास भी हासिल कर लिया था, उच्च न्यायालय के अनुसार, जब वह ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित हुआ तो

उसने स्वीडन के अधिवास को त्याग दिया और इस तरह भारत का अधिवास पुनर्जीवित हो गया। इस संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "15.4..... यह इस तथ्यात्मक मैट्रिक्स के खिलाफ है, हम संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी यह स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि उसने कभी भी भारतीय अधिवास को त्याग किया था और/या अपनी पसंद का अधिवास प्राप्त करने का इरादा रखता था।
>
> 16. भले ही यह भी मान लिया जाए कि प्रतिवादी ने अपना मूल निवास स्थान छोड़ दिया था और 1997 में नागरिकता के साथ-साथ स्वीडन का अधिवास भी हासिल कर लिया था, लेकिन जब प्रतिवादी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित हुआ तो उसने स्वयं ही स्वीडन का अधिवास त्याग दिया। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा बताए गए मामले को ध्यान में रखते हुए और जहां तक ऑस्ट्रेलियाई अधिवास के अधिग्रहण का संबंध है, हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि उनके स्वीडिश अधिवास को त्यागने पर भारत का अधिवास तुरंत पुनर्जीवित हो गया..."

07. यह इस आदेश के विरुद्ध है कि पति न्यायालय की अनुमति से के साथ हमारे समक्ष उपस्थित है।

08. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरी और श्री वाई.एच. मुछाला और श्री हुज़ेफ़ा अहमदी को सुना। प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गिरि हमारा ध्यान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की ओर आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि यह अधिनियम केवल भारत में रहने वाले हिंदुओं पर लागू होगा। उनका कहना है कि जो पार्टियां अब भारत की निवासी नहीं रह गई हैं, वे इस अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगी। श्री मुछाला इस मुद्दे से जुडते हैं और तर्क देते हैं कि इस अधिनियम का लाभ भारत में रहने वाले हिंदुओं द्वारा उठाया जा सकता है, भले ही उनका अधिवास कुछ भी हो। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर इस न्यायालय की कोई प्रिसिडेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के बड़ी संख्या में फैसले उनके तर्क का समर्थन करते हैं। इस संबंध में, वह प्रेम सिंह बनाम श्रीमती दुलारी बाई और अन्य मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। एआईआर 1973 कैल. 425, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "उपरोक्त प्रावधानों को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, पहले खंड से यह स्पष्ट लगता है कि अधिनियम संपूर्ण भारत पर

लागू है। जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर यह उन क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं पर भी लागू होता है, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जो उक्त क्षेत्रों के बाहर हैं। धारा 2(1)(ए)(बी) के साथ पढ़ा गया यह खंड यह समान रूप से स्पष्ट करता है कि जहां तक अधिनियम के राज्यक्षेत्रातीत संचालन का संबंध है, यह सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों या सिखों पर लागू होता है, चाहे वे भारत के अधिवासी हों या नहीं।

9. निताबेन बनाम धीरेंद्र चंद्रकांत शुक्ला और अन्य 1984 डी.एम.सी. 252 मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है। हमारा ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया गया है:

"स्पष्ट रूप से देखने पर, श्री नानावटी का यह तर्क आकर्षक है। लेकिन यह नहीं भुलाया जाएगा कि अधिनियम की धारा-1 जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू अधिनियम के विस्तार का उल्लेख करती है और साथ ही उन क्षेत्रों का भी जिनमें अधिनियम लागू है, और इसके अलावा उन सभी व्यक्तियों पर जो उन क्षेत्रों के आदिवासी हैं लेकिन जो उक्त क्षेत्रों से बाहर हैं।"

10. एक और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय जिसका संदर्भ दिया गया है वह है वरिन्द्र सिंह एवं अन्य आर.एल.डब्ल्यु 2005(3) राज. 1791 का पैराग्राफ 13 और 17 जो प्रासंगिक हैं उसे इस प्रकार पढ़ें:

> "13. 1955 के अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) का खंड (ए) 1955 के अधिनियम को उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो धर्म से हिंदू हैं, चाहे वे कहीं भी निवास करते हों।
>
> xxx xxx xxx
>
> 17. इसलिए, 1955 के अधिनियम की धारा 2 उन सभी व्यक्तियों को सम्मलित करने के लिए काफी व्यापक है जो धर्म से हिंदू हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वे कहां निवास कर रहे हैं और वे भारतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं या नहीं।

11. अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने विनय नायर और अन्य बनाम कोच्चि निगम एआईआर 2006 केरल 275 मामले में केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा जताया है और हमारा ध्यान फैसले के पैराग्राफ 6 से निम्नलिखित अंश की ओर आकर्षित किया गया है जो इस प्रकार है:

"अधिनियम की धारा 1 और 2 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि जहां तक अधिनियम की धारा 1(2) के दूसरे अंग का संबंध है, अधिनियम का अंतर-क्षेत्रीय संचालन उन लोगों पर लागू होता है जो क्षेत्रों के बाहर निवास करते हैं। धारा-1 की उप-धारा (2) और धारा.2(1) के खंड (ए) और (बी) का पहला भाग यह स्पष्ट करेगा कि अधिनियम भारत में रहने वाले हिंदुओं पर लागू होगा, चाहे वे इस क्षेत्र के बाहर निवास करते हों या नहीं।"

12. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण के लिए अधिनियम की सीमा और प्रयोज्यता की जांच आवश्यक है। अधिनियम की धारा 1(2) अधिनियम की सीमा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। वही इस प्रकार पढ़ी जाती है:

"1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार.-

(1) xx xx xx

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में है, और यह उन क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं पर भी लागू होता है जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, जो उक्त क्षेत्रों से बाहर हैं।"

13. अधिनियम की धारा 1(2) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसका संचालन अतिरिक्त प्रादेशिक/राज्येतर है। राज्यों की संप्रभुता में अंतर्निहित

सामान्य सिद्धांत यह है कि एक राज्य द्वारा बनाए गए कानून दूसरे राज्य में लागू नहीं हो सकते। एक कानून जिसका क्षेत्रीय प्रभाव से परे प्रभाव है, उसे सीधे दूसरे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कानून अमान्य नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 (2) द्वारा संरक्षित है। अनुच्छेद 245(2) में प्रावधान है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि इसका संचालन राज्यक्षेत्रातीत होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिसका भारत से कोई संबंध ही न हो। हमारी राय में, जब तक ऐसी आकस्मिकता मौजूद न हो, संसद अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन वाला कानून बनाने में अक्षम होगी। इस संबंध में इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त एवं अन्य। 1989 अनुपूरक (2) एससीसी 642 जिसमें इसे इस प्रकार आयोजित किया गया है:

> "9. लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में किसी चीज के साथ संबंध जरूरी है। हमें ऐसा लगता है कि जब तक एेसा संबंध मौजूद नहीं होगा, संसद के पास कानून बनाने की कोई क्षमता नहीं होगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 245(1) संसद को भारत के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता

है। कानून के लिए आवश्यकता का कारण भारत के भीतर ही खोजा जाना चाहिए। इस तरह के कानून में उद्देश्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन हो सकता है, और वह उद्देश्य भारत की किसी चीज से संबंधित होना चाहिए। यह समझ से बाहर है कि भारत में संसद द्वारा एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसका भारत में किसी भी चीज़ से कोई संबंध न हो।"

14. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जब हम अधिनियम की धारा 1(2) पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत के हिंदुओं पर लागू होता है। संक्षेप में, हमारी राय में, यह अधिनियम भारत में रहने वाले हिंदुओं पर लागू होगा, भले ही वे भारत से बाहर रहते हों। यदि भारत में निवास की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, तो अधिनियम का भारत के साथ कोई संबंध नहीं होगा जो इस आधार पर अधिनियम को कमजोर बना देगा कि अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन का भारत के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारी राय में, कानून के इस अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन को हिंदुओं के साथ संबंध के कारण नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हिंदुओं के कारण बचाया गया है।

15. इस स्तर पर, यहां नीचे उद्धृत आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

> "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारत में निवास की शर्त, जैसा कि हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 1(2) में विचार किया गया है, हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत राहत की मांग करने वाली याचिका को बनाए रखने के लिए आवश्यक घटक है। दूसरे शब्दों में, एक पत्नी, जो भारत में निवास करती है और हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत राहत की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत करती है, तो उसकी याचिका भारत के क्षेत्रों में और उस न्यायालय में, जिसके सामान्य नागरिक क्षेत्राधिकार में वह रहती है, स्थानीय सीमाओं के भीतर सुनवाई योग्य होगी।

16. अब, हम प्रतिवादी-पत्नी के वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किए गए उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर लौटते हैं; क्रम में पहला है प्रेम सिंह (सुप्रा) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय। इस मामले में, पति ने अन्य बातों के साथ-साथ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और दलील दी कि उसने अपनी पत्नी से भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी। शादी के बाद वे पति-पत्नी की तरह रहने लगे और एक बेटी का जन्म हुआ। पति की शिकायत यह

थी कि पत्नी ससुराल लौटने में विफल रही, जिसके कारण उसे वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन दायर करना पड़ा। विचारणीय न्यायालय ने पाया कि पति नेपाली था और वह भारत का मूल निवासी नहीं था और इसलिए, वह अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करवा सकता था। अधिनियम की धारा 1(1) और 2(1) की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने माना कि अधिनियम के अंतर-क्षेत्रीय संचालन के संबंध में, यह स्पष्ट है कि यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है, चाहे वे भारत में निवासरत हैं या नहीं। अपने सबसे गहन विचार के बाद, हम इतनी व्यापक अवधि में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन करने में असमर्थ हैं। यदि इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो दुनिया में कहीं भी रहने वाला हिंदू अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के संबंध में भारत में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। यह कहना कि यह हिंदुओं पर उनके अधिवास की परवाह किए बिना लागू होता है, बिना किसी सांठगांठ के पूरे विश्व में अधिनियम के अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन का विस्तार करता है, जिसकी व्याख्या यदि अनुमोदित हो जाती है, तो ऐसा प्रावधान अमान्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, इससे अधिनियम की धारा 1(2) में "अधिवासित" शब्द निरर्थक हो जाएगा। विधायिका आमतौर पर अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं करती, यह व्याख्या का एक स्वीकृत सिद्धांत है। कोई अन्य व्याख्या 'अधिवास' शब्द को निरर्थक बना देगी। इसलिए, हमारी राय में, कलकत्ता उच्च न्यायालय

का निर्णय यह मानते हुए कि अधिनियम के प्रावधान एक हिंदू पर लागू होंगे, चाहे वह भारत के क्षेत्र में अधिवासित हो या नहीं, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति अधिनियम की प्रयोज्यता को स्वीकार कर सकता है यदि एक पक्ष भारतीय अधिवास का हिंदू है और दूसरा पक्ष अधिनियम द्वारा शासित होने के लिए स्वेच्छा से हिंदू है।

17. जहां तक निताबेन (सुप्रा) में पत्नी द्वारा भरोसा किए गए गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के अंश का संबंध है, यह नहीं बताता है कि अधिनियम सभी हिंदुओं पर लागू होता है, चाहे वे भारत में अधिवासित हों या नहीं। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने माना है कि यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो भारत के निवासी हैं।

18. जहां तक वरिन्द्र सिंह (सुप्रा) मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले का सवाल है, यह सच है कि अधिनियम की धारा 1(2) के तहत, भारत में निवास आवश्यक नहीं है और धारा 2 भी आवश्यकता के बारे में बात नहीं करती है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस फैसले में ठीक यही कहा है, लेकिन, हमारी राय में, विद्वान न्यायाधीश जिस बात पर ध्यान देने में विफल रहे, वह यह है कि अधिनियम का अनुप्रयोग तभी सामने आएगा जब अधिनियम उस क्षेत्र तक विस्तारित होगा। इसलिए, हमारी राय में, राजस्थान उच्च न्यायालय का एफ निर्णय

कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। इसी कारण से, हमारे विचार में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय ग़लत है।

19. धारा 2(1) अधिनियम के लागू होने का प्रावधान करती है। जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः-

2. अधिनियम का लागू होना.-

(1) यह अधिनियम लागू होता है -

(ए) किसी भी व्यक्ति को, जो किसी भी रूप या विकास में धर्म से हिंदू है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज का अनुयायी शामिल है

(बी) किसी भी व्यक्ति को जो किसी धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है, और

(सी) उन क्षेत्रों में निवास करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हिंदू कानून या किसी अन्य प्रथा द्वारा शासित नहीं होता।

20. यह धारा अधिनियम के किसी भी रूप में धर्म के अनुसार हिंदू या विस्तारित अर्थ वाले हिंदू जैसे बौद्ध, जैन या सिख पर लागू होने पर विचार करती है और वास्तव में, देश में रहने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू होती है जो मुस्लिम नहीं हैं। ईसाई, पारसी या यहूदी, जब तक यह

साबित न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रथा या प्रथा के तहत अधिनियम द्वारा शासित नहीं होते हैं। इसलिए, हमारे विचार में धारा 2 हिंदुओं पर तब लागू होगी जब अधिनियम की धारा 1 के संदर्भ में अधिनियम उस क्षेत्र तक विस्तारित होगा। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, अधिनियम भारत के क्षेत्र के बाहर के हिंदू पर तभी लागू होगा जब ऐसा हिंदू भारत के क्षेत्र में अधिवासित हो।

21. इस बात पर ज्यादा विवाद नहीं है कि याचिका प्रस्तुत करने के समय पत्नी भारत की निवासी थी। याचिका को स्वीकार्यता के आधार पर पराजित करने के लिए, श्री गिरि ने कहा कि पत्नी पति के अधिवास का पालन करेगी जब स्वीडन पसंद का अधिवास बन गया है, मूल अधिवास यानी भारत समाप्त हो गया है। पति के अनुसार, पक्षों का मूल निवास भारत था, लेकिन 1987 में पति स्थायी रूप से वहां रहने के इरादे से स्वीडन चले गए और अपनी पसंद के अधिवास के रूप में स्वीडिश अधिवास हासिल कर लिया। शादी के बाद, पत्नी भी स्थायी रूप से रहने के लिए स्वीडन चली गई और दोनों ने 1996-97 में स्वीडिश नागरिकता हासिल कर ली, जिससे उन्होंने अपना मूल निवास स्थान छोड़ दिया और स्वीडन को अपनी पसंद के अधिवास के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके अलावा, पत्नी की अंग्रेजी भाषी देश में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त करने के कारण परिवार स्थायी रूप से वहां रहने के इरादे से जून, 1999 में ऑस्ट्रेलिया चला गया और ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवासी का दर्जा हासिल

करने की प्रक्रिया शुरू की। इन तथ्यों पर, पति यह तर्क देना चाहता है कि उन्होंने पसंद के अधिवास के रूप में स्वीडिश अधिवास प्राप्त किया है। हालाँकि, श्री मुछाला का कहना है कि पति का विशिष्ट मामला यह है कि वह ऑस्ट्रेलिया के अधिवास वाला एक स्वीडिश नागरिक है और इसलिए, अपीलकर्ता को यह दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह स्वीडन का अधिवासी है। वह बताते हैं कि पति यह अच्छी तरह से जानते हुए भी यह प्रयास कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का मूल अधिवासी होने का उसका दावा स्वीकार्य नहीं है और इस आकस्मिकता में वह यह तर्क दे रहा है कि पसंद का पिछला निवास स्थान, यानी स्वीडन पुनर्जीवित हो गया है।

22. हमने प्रतिद्वंद्वी के पुनर्जीवित होने वाले तर्क को माना है और हमें श्री मुछाला के तर्क में दम नजर आता है। कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में, कानून वैकल्पिक याचिका दायर करने की अनुमति देता है लेकिन वर्तमान मामले के तथ्य पति को यह रास्ता अपनाने की अनुमति नहीं देते हैं। अपीलकर्ता का यह विशिष्ट मामला है कि वह ऑस्ट्रेलिया के अधिवास वाला एक स्वीडिश नागरिक है और यह ऑस्ट्रेलियाई अदालतों का क्षेत्राधिकार मामले में होगा। सफल होने के लिए, अपीलकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि वह ऑस्ट्रेलिया का अधिवासी है और, हमारी राय में, उसे तीसरा मामला बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि यह साबित नहीं होता है कि वह ऑस्ट्रेलिया का अधिवासी है, तो उसका पहला मामला पसंदीदा अधिवास, यानी स्वीडन, को पुनर्जीवित किया गया है। इस

संबंध में, हम इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए कथन को पुन: प्रस्तुत करना समीचीन समझते हैं:

> "22.....तत्काल मामले में, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1996 में आवेदक ने स्वीडन की नागरिकता और अधिवास प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में अधिवासित है। इस प्रकार, हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है इसमें शामिल पक्षों और फैमिली कोर्ट मुंबई के पास इस मामले में आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और याचिका हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है।"

23. अपीलकर्ता ने आगे कहा है कि पार्टियों ने कभी भी पसंद का तीसरा अधिवास हासिल नहीं किया है, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> "19...तत्काल मामले में, पसंद के अधिवास अर्थात् ऑस्ट्रेलिया अधिवास को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और न ही पार्टियों ने पसंद का तीसरा अधिवास प्राप्त किया है या मूल अधिवास को फिर से प्राप्त किया है.... ....

24. इसके अलावा, पति ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 1989 में शादी के समय, वह स्वीडन का निवासी था, लेकिन यह उसका मामला नहीं

है कि वह स्वीडिश कानून द्वारा शासित होगा या स्वीडिश अदालतों का क्षेत्राधिकार होगा। इस संबंध में उनके विशिष्ट साक्ष्य इस प्रकार हैं:

> "7...चूंकि यहां पक्षकार ऑस्ट्रेलिया में अधिवास वाले स्वीडिश नागरिक हैं, और इसलिए केवल ऑस्ट्रेलिया की अदालतों को ही इस प्रकृति की याचिका पर विचार करने का अधिकार है...।"

25. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता स्वीडन का अधिवासी होने का दावा नहीं करता है बल्कि ऑस्ट्रेलिया का अधिवास होने का दावा करता है और इसलिए, एकमात्र प्रश्न जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया उसके पति की पसंद का अधिवास है।

26. अधिवास तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात् मूल अधिवास कानून के क्रियान्वयन द्वारा अधिवास और पसंद का अधिवास। वर्तमान मामले में, हम केवल मूल के अधिवास और पसंद के अधिवास पर विचार कर रहे हैं। मूल निवास स्थान आवश्यक रूप से जन्म स्थान नहीं है। माता-पिता की उनके अधिवास से अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान किसी स्थान पर बच्चे का जन्म होने पर जन्म स्थान बच्चे का अधिवास नहीं माना जाएगा। पसंद के अधिवास में एक को छोड़ दिया जाता है और दूसरा अधिवास प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन उसके लिए, दूसरे अधिवास का अधिग्रहण पर्याप्त

नहीं है। मूल अधिवास तब तक कायम रहता है जब तक न केवल दूसरा अधिवास प्राप्त कर लिया जाता है, बल्कि मूल अधिवास को छोड़ने का इरादा भी प्रकट होना चाहिए। यह स्थापित करने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया उनकी पसंद का अधिवास स्थान है, पति ने अपने आवासीय किरायेदारी समझौते दिनांक 25.01.2003, 18 महीने की अवधि का पर भरोसा किया है। अप्रैल, 2003 में वार्रावी पब्लिक स्कूल में नताशा का नामांकन; अक्टूबर-नवंबर, 2003 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवासी का दर्जा देने के लिए कार्यवाही की शुरुआत; और ऑस्ट्रेलिया में अपना स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पति और पत्नी द्वारा बी 11.11.2003 को आवेदन जमा करना।

27. जन्म के अधिवास को बदलने का अधिकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध है जो कानूनी रूप से आश्रित नहीं है और ऐसा व्यक्ति पसंद का अधिवास प्राप्त कर सकता है। यह पसंद के देश में अनिश्चित काल तक निवास जारी रखने के इरादे से रहने के द्वारा किया जाता है। जब तक सिद्ध न हो, निवास स्थान परिवर्तन के विरुद्ध उपधारणा है। इसलिए आरोप लगाने वाले को यह साबित करना होगा। इरादा हमेशा दिमाग में रहता है, जिसका अनुमान ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी कार्य, घटना या परिस्थिति से लगाया जा सकता है। लंबी अवधि के लिए निवास, ऐसे इरादे का प्रमाण है और राष्ट्रीयता में परिवर्तन भी।

28. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जब हम ऑस्ट्रेलिया के निवासी होने के पति के दावे पर विचार करते हैं तो हमें इस दलील का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती है। आवासीय किरायेदारी समझौता केवल 18 महीने के लिए होता है जिसे लंबी अवधि के लिए नहीं कहा जा सकता। स्वीकृत है कि, पति व इस मामले में, पत्नी और बच्चों ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता हासिल नहीं की है। इसके अभाव में, यह स्वीकार करना कठिन है कि उनका इरादा ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से निवास करने का था। उपलब्ध सामग्री के सामने यह दावा कि पति ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से निवास करना चाहता था, केवल एक सपना ही कहा जा सकता है। इससे वहां स्थायी रूप से निवास करने का उनका इरादा स्थापित नहीं होता है।' पति ने स्वीकार किया है कि उसका वीज़ा और कुछ नहीं बल्कि एक "दीर्घकालिक परमिट" था और "कोई अधिवास दस्तावेज़ नहीं"। इतना ही नहीं, इस बात का भी कोई अंकन नहीं है कि पति ने मूल अधिवास को कैसे और किस तरह छोड़ दिया। इसके सामने, हमें पति के मामले को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि वह ऑस्ट्रेलिया अधिवासी है और वह मूल यानी भारत का निवासी बना रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे उत्तर में कि पति भारत का अधिवासी है, यह प्रश्न कि पत्नी पति के अधिवास का पालन करेगी, अकादमिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इन सभी कारणों से, हमारी राय है कि पति और पत्नी दोनों भारत अधिवासी हैं और इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत आएंगे। वास्तव में,

हमने पाया है कि दोनों पति-पत्नी भारत के मूल अधिवासी हैं, और अधिनियम उन पर लागू होगा। पार्टियों की ओर से उठाए गए अन्य तर्क अकादमिक हैं और हम उनका जवाब देना उचित नहीं समझत।

29. परिणामस्वरूप, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे तदनुसार खारिज कर दिया गया, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

2007 की सिविल अपील संख्या 487

30. 2005 की सिविल अपील संख्या 4629 (सोंडूर गोपाल बनाम सोंदुर रजनी) में हमारे फैसले के मद्देनजर, जिसमें कहा गया है कि बच्चों के न्यायिक अलगाव और अभिरक्षा के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका कायम रखने योग्य है, हमारी राय है कि कुछ इसी तरह की राहत के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर की गई रिट याचिका निरर्थक हो गई है। केवल इसी आधार पर, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हैं।

बी.बी.बी.

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुश्री अंशुल शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।